

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज

भोपाल, शनिवार 26 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित वर्ष-14 अंक-110 पृष्ठ-8 मूल्य- रु.5/-

PM Modi: India Is Driving Next-Generation Reforms in Policy and Governance

From Licence Raj to Incentives; Trust-Based Rules and Ease of Living at ET World Leaders Forum

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi told the Economic Times World Leaders Forum 2026 that India is implementing next-generation reforms at the policy level and undertaking reforms at the governance level.

"Reforms are not a compulsion for us; this is our ultimate commitment," he said. The government, he added, is shaping policies that are pro-people, pro-growth and pro-development. He contrasted the old Licence Raj, which he called a punishment model for production, with today's incentive approach.

The Prime Minister cited the Production Linked Incentive scheme as evidence of the shift. He said it has attracted ₹2.5 lakh crore in investment, driven ₹22 lakh crore in production and sales, generated ₹15 lakh crore in exports and created over 14 lakh jobs.

On governance, he said the rulebook is moving from "prohibited unless permitted" to "permitted unless prohibited." The relationship between the state and citizens, he said, must rest on trust, not suspicion. More than 40,000 compliances have been removed and over 1,500 obsolete laws repealed. The Jan Vishwas framework has replaced jail for many minor procedural offences with economic penalties.

He also pointed to drone deregulation, defence self-reliance, digital public services and rooftop solar under the Surya Ghar scheme. Political stability and policy continuity, he argued, give India the space to keep the "reform express" moving and offer the world a more secure partner for shared growth.

बेंगलुरु में सीएम यादव का निवेशकों से संवाद, ₹1,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले

ग्वालियर टीएमजेड में पहले से ₹5,000 करोड़, दूसरे चरण की तैयारी; 20 हजार रोजगार की संभावना

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 सितंबर को बेंगलुरु में उद्योगपतियों और प्रमुख निवेशकों से वन-टू-वन संवाद किया। बैठक में मध्य प्रदेश को करीब ₹1,200 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव मिले।

चर्चा का केंद्र ग्वालियर टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग ज़ोन रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ज़ोन को लेकर निवेशकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। ज़ोन में अब तक लगभग ₹5,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। भूमि लगभग भर चुकी है। अगले एक-दो महीने में दूसरे चरण का काम शुरू होने की संभावना है।

नए प्रस्तावों से करीब 20 हजार रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है। संवाद में चिप डिजाइन, ड्रोन तकनीक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में राज्य की संभावनाओं पर भी बात हुई। सरकार टेलीकॉम और संबंधित विनिर्माण के साथ तकनीक आधारित उद्योग बढ़ाने पर जोर दे रही है।

ग्वालियर टीएमजेड को दूरसंचार उपकरण निर्माण का केंद्र बनाने की योजना है। बेंगलुरु आईटी-इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का बड़ा आधार है, इसलिए वहां से निवेशकों से सीधा संवाद राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना गया। प्रस्तावों को परियोजना में बदलने के लिए भूमि आवंटन, मंजूरी और बिजली-कनेक्टिविटी तय करने वाले होंगे।

यह दौरा जीआईएस 2027 से पहले राज्य के निवेश अभियान का हिस्सा है। टीएमजेड का विस्तार मध्य प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने का प्रयास है। प्रस्तावों का क्रियान्वयन ही वास्तविक निवेश और रोजगार तय करेगा।



WE ARE HIRING!

BUSINESS GROWTH MANAGER

Join our dynamic team and be a part of a **growing legacy**.

- EXPERIENCE**
3-5 Years
- QUALIFICATION**
MBA / MJMC
- CTC**
3-5 Lacs per annum

WHY JOIN US?

- Be part of a trusted brand in financial journalism
- Work in a dynamic and growth-oriented environment
- Excellent learning and growth opportunities
- Performance based rewards

APPLY NOW

SEND RESUME TO editor@investmentavenues.in

CONTACT NO. **9238363255**

WEBSITE www.investmentavenues.in

ADDRESS E4 Arera Colony, Dutt Mandir Campus, Bhopal-462016

MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज)

(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

YOUR DAILY GUIDE TO STOCK MARKET & BUSINESS NEWS

मध्य प्रदेश ने भव्य योजना के तहत 11 औद्योगिक पार्कों का प्रस्ताव रखा ₹8,144 करोड़ की लागत, 9,000 एकड़ से अधिक भूमि पर तैयार-ड्रेजिंग सुविधाएं

प्रधानमंत्री मोदी के 'शक्ति की सुधार', मिशन को सकार करने का संकल्प: सिद्धार्थ सिंह चौहान

कमजोर मानसून से बड़ी खाद्य महंगाई, लेकिन ग्रामीण मांग मजबूत: नोमुरा

Cabinet Clears ₹13,041 Crore Rail and Road Projects

TRUSTED NEWS | SHARP INSIGHTS | SMART DECISIONS | BETTER TOMORROW

एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 26 का अंतिम लाभांश ₹3,394 करोड़ चुकाया

कुल भुगतान ₹8,727 करोड़, प्रति शेयर ₹9; लगातार 33वें वर्ष लाभांश

नई दिल्ली: सरकारी बिजली उत्पादक एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2025-26 का अंतिम लाभांश ₹3,393.83 करोड़ चुका दिया है। इससे पूरे वर्ष का कुल लाभांश भुगतान ₹8,727 करोड़ हो गया है। अंतिम किस्त 23 सितंबर को दी गई। कंपनी के अनुसार यह चुकता इक्विटी पूंजी का 35 प्रतिशत है। इसके अलावा नवंबर 2025 और फरवरी 2026 में दो अंतरिम लाभांश ₹2,666.58 करोड़-₹2,666.58 करोड़ पहले ही दिए जा चुके थे। कुल भुगतान प्रति इक्विटी शेयर ₹9 के बराबर है। शेयर का अंकित मूल्य ₹10 है। यह एनटीपीसी द्वारा लगातार 33वां वर्ष है जब शेयरधारकों को लाभांश मिला है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उत्पादक है।

स्थापित क्षमता 91 गीगावॉट से अधिक है और 35 गीगावॉट से अधिक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 2032 तक 149 गीगावॉट का लक्ष्य है, जिसमें 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। देश की लगभग एक-चौथाई बिजली मांग एनटीपीसी पूरी करती है। बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभांश से केंद्र के राजस्व को सहारा मिलता है। एनटीपीसी का भुगतान पारंपरिक ताप क्षमता के साथ हरित विस्तार के बीच नकदी प्रवाह बनाए रखने की क्षमता दर्शाता है। क्षमता वृद्धि, ईंधन लागत और नवीकरणीय परियोजनाओं का निष्पादन आगे की लाभप्रदता तय करेगा। शेयरधारकों के लिए यह नियमित आय का हिस्सा रहा है, जबकि कंपनी दीर्घकालिक विस्तार पर काम कर रही है।



जेपी मॉर्गन गिफ्ट सिटी कारोबार दोगुना करेगी, बुक 1 अरब डॉलर के पार ट्रेजरी, ट्रेड फाइनेंस और भुगतान पर जोर; बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मांग बढ़ी

मुंबई: जेपी मॉर्गन चेस गिफ्ट सिटी में अपना कारोबार अगले दो वर्षों में दोगुना करने की योजना बना रही है। बैंक की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र शाखा का बुक करीब 1 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और कुछ सौ ग्राहक जुड़े हैं।

ग्लोबल पेमेंट्स सह-प्रमुख मैक्स न्यूकिर्चने ने कहा कि शाखा चार वर्ष से काम कर रही है और कारोबार तेजी से बढ़ा है। जून में लंदन से वरिष्ठ अधिकारी अमित रॉय को गिफ्ट सिटी शाखा का प्रमुख बनाया गया। भारत में पेमेंट्स प्रमुख गुहप्रसाद राजगोपाल के अनुसार ट्रेजरी सेंटर बढ़ा विषय है। विदेशी मुद्रा खातों के साथ रुपये की सुविधा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अतिरिक्त आकर्षण है।

शाखा ट्रेड फाइनेंस, विदेशी मुद्रा, लिक्विडिटी, भुगतान, ऋण, जोखिम प्रबंधन,

वर्किंग कैपिटल, निवेश सेवाएं तथा फिक्स्ड इनकम और कमोडिटी उत्पाद देती है। ट्रेजरी के लिए फिजिकल पूलिंग, कैश कंसंट्रेशन और नोशनल पूलिंग भी उपलब्ध हैं। जुलाई में बैंक ने कहा था कि अगले 12-18 महीनों में 100 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बीमा और फिनटेक इकाइयां बैंकिंग-पेमेंट समाधान मांग रही हैं।

गिफ्ट सिटी आईएफएससी में बैंकिंग परिसंपत्तियां मार्च 2026 तक 111 अरब डॉलर रही। 1,500 से अधिक इकाइयां और करीब 27,000 पेशेवर काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ट्रेजरी सेंटरों के ऋण 5.61 अरब डॉलर थे। 37 बैंक सक्रिय हैं, जिनमें 20 विदेशी हैं।

जेपी मॉर्गन का विस्तार भारत की 7.8 प्रतिशत वृद्धि और एशिया रणनीति से जुड़ा है। कर-नियामकीय स्थिरता और प्रतिस्पर्धी सेवाएं ग्राहक बढ़ाने का आधार रहेंगी।



Oriental Insurance Bets on Health and MSME Covers to Drive Growth Surety Bonds Expanded; NSE Stake Sale to Aid Liquidity and Solvency

New Delhi: Oriental Insurance Company is pinning its next phase of growth on health insurance, cost-effective products for micro, small and medium enterprises, and a larger surety-bond book.

Chairman and Managing Director Sanjay Joshi said the general insurer needs affordable covers to deepen market penetration. In health, the company wants a more sustainable ecosystem in which hospitals are paid fairly, claims costs stay manageable and policyholders get timely cashless treatment at predictable prices. Plans include stronger provider networks, standardised package rates, tighter fraud controls and better grievance handling.

On the technology side, Oriental is building an API-driven architecture, a centralised

litigation system and a next-generation cybersecurity operations centre. Customer portals and the mobile app are being upgraded for faster service.

The insurer has also entered surety bonds, offering bid, performance, advance mobilisation, retention, customs and court bonds under Oriental Surety Bond Insurance. The product is aimed at contractors and infrastructure players who need guarantees instead of Separately, Oriental is unlocking part of its 1.42 per cent holding in the National Stock Exchange. It has put up 4.96 million of its 35.2 million NSE shares in the exchange's ₹22,562 crore IPO, valued at about ₹885 crore at ₹1,875 a share. Joshi said the listing gives original shareholders a chance to realise value and improve liquidity and solvency.

Public-sector general insurers have faced combined-ratio pressure in health. Oriental's bet is that retail health, MSME packages and surety can widen the book while the NSE sale strengthens the balance sheet.

Oriental Health Insurance



जबलपुर-भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनेगा प्रदेश का ग्रोथ इंजन, 2 लाख नौकरियां

18 हजार करोड़ से अधिक के एक्सप्रेस-वे पर चार औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल टाउनशिप और स्किल सिटी; यात्रा समय लगभग आधा

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर-भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को केवल सड़क नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को बताया कि इस मार्ग पर चार बड़े औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल टाउनशिप और स्किल सिटी विकसित की जाएंगी। अनुमान है कि इससे दो लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। परियोजना की कुल लागत 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे की लंबाई 161 किलोमीटर है। छह लेन का एक्सेस-कंट्रोल ग्रीनफील्ड मार्ग पुरानी बसाहटों और ट्रैफिक से दूर बनेगा। वर्तमान चार घंटे का सफर घटकर दो से ढाई घंटे रह जाएगा। भोपाल-जबलपुर कॉरिडोर लगभग 255 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी प्रस्तावित लागत 14,105 करोड़ रुपये है। इससे छह घंटे की यात्रा तीन से साढ़े तीन घंटे में पूरी होने की उम्मीद है। इंदौर-भोपाल खंड की लागत करीब 9,716 करोड़ रुपये बताई गई है।



उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप के अनुसार यह राजमार्ग औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। चार स्थानों पर बड़े औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे और कौशल विकास के लिए अलग स्किल सिटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल सिटी विकसित मध्य प्रदेश की नई पहचान बनेगी। यहां हर साल 50 हजार से अधिक युवाओं का कौशल विकास और क्षमतावर्धन होगा।

सरकार का तर्क है कि तेज कनेक्टिविटी से निवेशक, लॉजिस्टिक्स और सहायक उद्योग आकर्षित होंगे। टाउनशिप में उद्योग के साथ आवास और शहरी सुविधाएं जुड़ने से प्रवास और स्थानीय रोजगार दोनों बढ़ सकते हैं। युवाओं के लिए कौशल केंद्र इसलिए जरूरी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम के अनुरूप प्रशिक्षित हाथ उपलब्ध रहें।

निवेशकों के लिए यह घोषणा भूमि, ऑफटेक और निष्पादन पर निर्भर दीर्घकालिक दांव है। ग्रीनफील्ड मार्ग पर औद्योगिक पार्क तभी सफल होते हैं जब बिजली, जल, लैंड टाइटल और सिंगल-विंडो मंजूरी समय पर मिलें। यदि चार क्षेत्र और स्किल सिटी योजना के अनुरूप बनते हैं तो मध्य भारत का यह गलियारा विनिर्माण और रोजगार का नया केंद्र बन सकता है। काम जल्द शुरू करने का संकेत दिया गया है।

क्या ₹15,000/महीने की SIP बना सकती है ₹1 करोड़+?

15 × 15 × 15

RULE

₹15,000/
महीना SIP
(इक्विटी म्यूचुअल फंड में)



15%
सालाना रिटर्न



15 साल
(लगातार निवेश)



15 साल बाद
संभावित वेल्थ

1 करोड़+

₹27 लाख कुल निवेश

₹75+ संभावित वेल्थ गेन

एक-एक SIP से बनाएं बड़ी वेल्थ।

*म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। सभी आंकड़े अनुमानित हैं और केवल उदाहरण के लिए हैं।



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com



आपने 10 साल नहीं गंवाए।

आपने ₹1.23 करोड़ गंवाए।

30 साल की उम्र में ₹10,000/माह की SIP, 12% रिटर्न के साथ शुरू की।

उम्र 55 ~ ₹1.70 करोड़।



40 साल की उम्र में ₹10,000/माह की SIP, 12% रिटर्न के साथ शुरू की।

उम्र 55 ~ ₹47 लाख।



₹1.23 करोड़

आइए शुरुआत करें, इससे पहले कि यह अंतर और बढ़ जाए।



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com



Maruti Turns Surplus Solar into Green Hydrogen at Manesar Pilot Plant

300 kW electrolyser blends GH2 with natural gas for factory fuel; company also scales biogas, CBG and battery storage

Mumbai: Maruti Suzuki India has commissioned a 300-kW green hydrogen electrolyser at its Manesar plant in Haryana, its first such facility and a pilot for cleaner manufacturing. Surplus solar power from the campus especially on holidays when factory demand is low—will run the electrolyser. The hydrogen will be stored and blended with natural gas as process fuel on the shop floor.

The company said the project maximises on-site solar that would otherwise go unused and will generate operating lessons before a wider rollout across plants in Haryana and Gujarat. Managing Director and CEO Hisashi Takeuchi said Maruti is taking a multi-pathway approach to energy in manufacturing, just as it does for vehicles, and that the pilot aligns with India's National Green Hydrogen Mission. The mix already includes rooftop and ground solar, renewable power from government sources and third-party solar and wind purchase agreements.

Maruti is also advancing biogas and storage. A 10-tonne-per-day biogas plant at Kharkhoda is in an advanced stage and is due in FY27. The same site already has a 1 MWh battery energy storage system. The automaker has begun using compressed biogas as process fuel and has approved four CBG projects with a budget of Rs 5,610 million. Parent Suzuki Motor Corporation has partnered the National Dairy Development Board and dairy unions for 10 biogas plants in India; three are already running in Gujarat.

The Manesar unit is small relative to a full-scale hydrogen economy. The company has not disclosed tonnes-per-day output. Its value is as a test of electrolyser operations, blending ratios, storage and safety inside an auto factory. If the economics work, hydrogen becomes another way to firm renewable power and cut fossil gas in heat and process uses.

For investors, the announcement is incremental to Maruti's larger capex and volume story, not a new product line. Shares were little changed after the filing. The signal is that India's largest carmaker is treating plant emissions as a multi-technology problem solar, storage, biogas and now green hydrogen rather than a single-fuel bet. Scale-up will depend on cost, reliability and policy support under the Green Hydrogen Mission.



एड्रॉइट इंडस्ट्रीज आईपीओ 25 सितंबर तक खुला, मूल्य बैंड 126-134 रुपये 151 करोड़ रुपये का निर्गम; रिटेल लॉट 111 शेयर, ऊपरी कीमत पर न्यूनतम निवेश 14,874 रुपये; लिस्टिंग 30 सितंबर को

एड्रॉइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम 23 सितंबर को खुला और 25 सितंबर 2026 तक आवेदन लिए जाएंगे। यह बुक-बिल्ट इश्यू करीब 151 करोड़ रुपये का है। इसमें 98.97 लाख नए शेयरों से लगभग 133 करोड़ रुपये और प्रवर्तक मुकेश सांगला (एचयूएफ) के 13.50 लाख शेयरों की बिक्री से करीब 18 करोड़ रुपये शामिल हैं। मूल्य बैंड 126 से 134 रुपये प्रति शेयर है, अंकित मूल्य 10 रुपये।

लॉट साइज 111 शेयर है। रिटेल निवेशकों को ऊपरी बैंड पर न्यूनतम 14,874 रुपये लगाने होंगे। आवंटन 28 सितंबर, रिफंड व डीमैट क्रेडिट 29 सितंबर और बीएसई-एनएसई पर लिस्टिंग 30 सितंबर को प्रस्तावित है। ऊपरी कीमत पर बाजार पूंजीकरण करीब 600 करोड़ रुपये बनेगा। नेट ऑफर में क्यूआईबी 50 प्रतिशत, एनआईआई 15 प्रतिशत और रिटेल 35 प्रतिशत है। एंकर निवेशकों से 22 सितंबर को 45.21 करोड़ रुपये जुटाए गए। बुक रनिंग लीड मैनेजर चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स और रजिस्ट्रार बिगशेयर सर्विसेज हैं।

कंपनी 1995 में बनी और प्रोपेलर शाफ्ट तथा ड्राइवलाइन के टॉर्क-ट्रांसमिशन पुर्जे बनाती है। पोर्टफोलियो में 5,000 से अधिक एसकेयू हैं। फोर्जिंग से लेकर मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, असेंबली और परीक्षण तक काम इन-हाउस होता है। उत्पाद वाणिज्यिक वाहन, एसयूवी, रक्षा, भारी उपकरण और औद्योगिक उपयोग में जाते हैं। वित्त वर्ष 2026 में 32 से अधिक देशों को निर्यात हुआ। जुलाई 2026 तक स्थायी कर्मचारी 367 थे।

वित्त वर्ष 2026 में कुल आय 143 करोड़ और लाभ 26.16 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष से लाभ में 44 प्रतिशत अधिक है। ताजा पूंजी देवास संयंत्र की मशीनरी, सहायक अड्रॉइट ड्राइवशाफ्ट्स के पीथमपुर विस्तार और ऋण चुकौती पर लगेगी। प्रवर्तक हिस्सेदारी निर्गम बाद करीब 72 प्रतिशत रह जाएगी।

ग्रे मार्केट प्रीमियम अनौपचारिक संकेत है और बदल सकता है। निवेशकों को ऑटो-कंपोनेंट चक्र, निर्यात मांग, कर्ज और मूल्यांकन देखकर निर्णय लेना चाहिए। यह लेख सूचना मात्र है, आवेदन सलाह नहीं।



IRDAI Plans Product-Wise Commission Caps, Tighter Expense Limits for Insurers

Consultation paper seeks feedback by October 25; life EoM to 12.5% and general to 20% in five years; banks and brokers face steeper cuts than agents

New Delhi: The Insurance Regulatory and Development Authority of India has proposed a sweeping reset of how insurers pay distributors and how much they can spend on management. A consultation paper titled "Recalibrating Economics of Insurance Distribution" links commission caps to product type, channel, policy size and selling effort, and sets a glide path to lower Expenses of Management. Comments are due by October 25.

For life insurers, Irdai proposes cutting EoM to 15% of premium in two years and 12.5% in five years. For general insurers the cap would fall from 30% now to 25% in two years and 20% in five years. Standalone health insurers would also face a tighter limit. The regulator says the aim is lower distribution and operating costs and better value for policyholders.

Commissions would no longer sit under a single flexible ceiling. On individual health policies, first-year commission is

proposed at 15% for distribution entities such as brokers and corporate agents and 20% for individual agents; renewals and portability would be 5% and 10%. Retail property insurance would follow similar first-year caps. Very large property and engineering risks with sum insured above ₹2,500 crore would attract only about 5-5.5%. Insurance sold with loans would have still lower limits, including around 5% on motor own-damage, personal accident, liability and first-year health.

In life insurance, first-year commission on individual policies with a premium-paying term of 10 years or more would be capped at 20% for distribution entities and 25% for agents. Shorter-pay policies would get lower first-year rates. Extra commission of 10-20% of the applicable cap is proposed for sales in smaller towns and rural areas.

Irdai has cited a sharp rise in commissions paid between FY23 and

FY25 and concerns over mis-selling. Industry executives warn that simultaneous cuts in commissions and EoM could squeeze growth for two to three years, hit bancassurance and brokers harder than agents, and favour large insurers with renewal books. Small players say they need a slower glide path. Insurance stocks fell after the paper. The proposals remain draft; the final rules will decide how deep the pinch is.



रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अधिकृत पूंजी चार गुनी होकर 40,000 करोड़ रुपये

उधार सीमा 27,000 करोड़; निवेश सीमा दोगुनी; कम्पा कोला और इंडिपेंडेंस ब्रांड्स के विस्तार के लिए पूंजी-ऋण दोनों की गुंजाइश

चेन्नई: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी एफएमसीजी इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) की अधिकृत शेयर पूंजी चार गुना बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दी है। कंपनी रजिस्ट्रार के नवीनतम फाइलिंग के अनुसार इससे पूंजी लगाने की गुंजाइश बढ़ेगी। आरसीपीएल कम्पा कोला और इंडिपेंडेंस श्रृंखला के स्टेपल बेचती है। कंपनी का कहना है कि बढ़ते एफएमसीजी संचालन के मद्देनजर पूंजी जारी करने की सुविधा के लिए यह बढ़ोतरी की गई है।

उधार सीमा भी तीन गुना बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपये कर दी गई है, जो पहले 9,000 करोड़ रुपये थी। अन्य कंपनियों में निवेश या ऋण देने की सीमा दोगुनी होकर 4,000 करोड़ रुपये हो गई है। आरसीपीएल बोर्ड ने जुलाई-अगस्त में प्रस्ताव मंजूर किए। तीन कार्यकारी निदेशकों टी. कृष्णकुमार, केतन मोदी और आसिम पारेख का कार्यकाल पांच वर्ष बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है।

पिछले दिसंबर में अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपये की गई थी। तब समूह के एफएमसीजी कारोबार का पुनर्गठन हुआ और यह रिलायंस

रिटेल वेंचर्स की बजाय सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक बन गई। ब्रांड रिलायंस रिटेल से स्थानांतरित हुए, पुरानी आरसीपीएल का विलय हुआ और उपभोक्ता ब्रांड उपक्रम नई इकाई में अलग होकर फिर आरसीपीएल नाम से चला।

दिसंबर 2025 से मार्च 2026 की अवधि में आरसीपीएल की कुल आय 7,042 करोड़ रुपये और शुद्ध घाटा 125 करोड़ रुपये रहा। फाइलिंग में वित्त वर्ष 2026-27 और आगे मूल्य व मात्रा दोनों में वृद्धि का सकारात्मक परिदृश्य बताया गया है। समूह ने पहले एफएमसीजी कारोबार के ईबीआईटीडीए पॉजिटिव होने का भी जिक्र किया था।

अधिकृत पूंजी बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि इतनी राशि तुरंत लगाई जाएगी। यह कानूनी छत है, जिससे जरूरत पड़ने पर इक्विटी जारी की जा सके। उधार सीमा बढ़ाने से कार्यशील पूंजी, विपणन, वितरण और इन्वेंटरी के लिए ऋण जुटाना आसान होगा। भारतीय एफएमसीजी बाजार में स्थापित दिग्गजों से टक्कर महंगी पड़ती है।

सफलता भूमि मंजूरी, निर्माण गति और किरायेदार भरने पर निर्भर

करेगी।

निवेशकों के लिए यह संकेत है कि रिलायंस उपभोक्ता सामान को दीर्घकालिक स्केल वाला व्यवसाय मान रही है। सफलता ब्रांड स्वीकृति, रिटेल नेटवर्क के उपयोग और घाटे को नियंत्रित रखने पर निर्भर करेगी। पूंजी की छत बड़ी है; असली परीक्षा खर्च का अनुशासन और बाजार हिस्सेदारी होगी।



वित्त वर्ष 27 में भारत जोड़ेगा करीब 8 गीगावाट पवन क्षमता: एमएनआरई

2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य; विनिर्माण 24 गीगावाट, निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश

नई दिल्ली: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि भारत चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 7.5 से 8 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने की राह पर है। संयुक्त सचिव राजेश कुल्हारी ने हैम्बर्ग में ईयू-इंडिया विंड एनर्जी बिजनेस समिट में यह बात कही। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 6 गीगावाट से अधिक क्षमता जुड़ी। 31 अगस्त 2026 तक देश की स्थापित पवन क्षमता 58.52 गीगावाट थी। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के बीच 2.42 गीगावाट जोड़ा जा चुका है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट पवन क्षमता का है, जो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य का हिस्सा है। कुल्हारी ने कहा कि क्षेत्र सीमित राजकोषीय सहायता के बावजूद गति पकड़ रहा है। पवन परियोजनाओं में निवेश करीब ₹7 करोड़ प्रति मेगावाट लगता है। घरेलू टर्बाइन विनिर्माण क्षमता लगभग 24 गीगावाट है, जो वार्षिक स्थापना से अधिक है। इससे निर्यात बढ़ सकता है। पिछले वर्ष पवन घटकों का निर्यात करीब ₹12,000 करोड़ रहा। भारत पहला ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। तमिलनाडु के समुद्र तट पर हवा की गति 10 मीटर प्रति सेकंड से अधिक बताई गई है, जिससे क्षमता उपयोग करीब 55 प्रतिशत संभव है। यूरोपीय कंपनियों के साथ तकनीक साझेदारी पर जोर दिया गया। भूमि, पारिषण और पुराने टर्बाइनों का रीपायरिंग लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी रहेगा। विनिर्माण अधिशेष निर्यात का अवसर है, बशर्ते गुणवत्ता और लॉजिस्टिक्स साथ दें।



Birla Bets ₹1,800 Crore on Wires and Cables After Cement Empire

Ultravolt Aims for Top-Two Slot in Five Years; Gujarat Plant and UltraTech Retail to Drive Reach

New Delhi: The Aditya Birla Group, long identified with cement through UltraTech, is putting ₹1,800 crore behind a wires and cables business branded Ultravolt. Chairman Kumar Mangalam Birla said wires and cables sit at the junction of urbanisation, electrification and digitisation. More than 100 million new homes over the next decade, expanding power networks and data centres are expected to lift demand. India's wires and cables market is estimated at about ₹90,000 crore and grew at around 13 per cent a year between FY19 and FY24. Demand is projected to rise 11-13 per cent annually through FY27. Ultravolt will make home wires, flexible wires and cables for residential, commercial, industrial and infrastructure use, and later add electrical accessories. A plant at Jhagadia in Gujarat's Bharuch district will feed a network of more than 20 warehouses. Initial distribution is planned across 500-plus districts and 6,000 pin codes, using UltraTech's reach of over one lakh retailers and 5,000 Building Solutions outlets. The group wants to be among the top two players in the segment within five years and says it is already targeting second place by capacity. The market remains fragmented, with nearly 400 producers and no firm holding more than 15 per cent

in wires. Organised players have gained share as quality and branding matter more. Ultravolt is the group's fourth new business in three years and can tap Hindalco for copper and aluminium. Execution will depend on dealer acceptance in a category still dominated by established electrical brands.



रेंटोमोजो का दमदार डेब्यू, IPO निवेशकों को मिला 19% का प्रीमियम 73 गुना सब्सक्रिप्शन ने बढ़ाया उत्साह, एनएसई पर 19% प्रीमियम के साथ शेयर की शानदार लिस्टिंग

Bengaluru: Enterprise artificial intelligence company Ema has raised \$77 million in a Series B round led by Creaegis, taking total funding to \$140 million.

Existing backers Accel, Section 32 and Prosus increased their stakes. The company said the round more than quadrupled its valuation from the previous financing in 2024. It did not disclose the new figure.

Founded in 2023 by former Coinbase and Google executive Surojit Chatterjee and former Okta executive Souvik Sen, Ema builds what it calls AI employees teams of agents that plan and run workflows across a company's existing HR, IT and finance systems.

Customers include NTT DATA, Hitachi, ADP, PwC, Google, KPMG, Wipro and Microsoft. Ema said it has more than 50 active enterprise

deals, over one million active users and has processed more than five million actions. At Wipro, it said an assistant supports more than 2,40,000 associates and handles about 2.9 million queries a year.

Revenue has grown 50-fold over two years, the company said, with bookings above \$150 million. Chatterjee noted that bookings include the full value of multi-year contracts, not annual recurring revenue.

Creaegis managing partner Prakash Parthasarathy said few agentic AI firms have shown production scale. The category is crowded with labs and software giants chasing the same enterprise budget.

फिजिक्सवाला के संस्थापक अलाख पांडेय दक्षिण भारत में रहकर कारोबार का विस्तार करेंगे अगले 24 महीने आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल पर फोकस; एमबीयू से समझौता

बेंगलुरु: एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला के संस्थापक और सीईओ अलाख पांडेय अगले 24 महीने दक्षिण भारत में रहकर कारोबार बढ़ाने वाले हैं। तिरुपति में छात्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह अवधि दक्षिण भारत के विद्यार्थियों को समर्पित रहेगी और वे यहीं तैनात रहेंगे।

उन्होंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में कंपनी की उपस्थिति बढ़ाने और अन्य राज्यों जैसी गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य बताया। पांडेय के अनुसार स्थापना से अब तक दक्षिण में मापने योग्य प्रभाव और बढ़ाने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को क्षमता साकार करने के साधन देने की बात कही गई।

पहले कदम के रूप में फिजिक्सवाला ने आंध्र प्रदेश की मोहन बाबू यूनिवर्सिटी से पांच वर्ष का समझौता किया है। इसके तहत विश्वविद्यालय

के करीब 18,000 छात्रों को ऑनलाइन एआई, स्किलिंग और करियर केंद्रित पाठ्यक्रम मिलेंगे। यह परीक्षा तैयारी से आगे बढ़कर संस्थागत साझेदारी का रास्ता है।

पांडेय और प्रतीक माहेश्वरी ने 2020 में कंपनी शुरू की। प्लेटफॉर्म पर अब तक 4 करोड़ छात्र जुड़े बताए गए हैं। वित्त वर्ष 26 में अकेले 50 लाख से अधिक भुगतान करने वाले छात्र नामांकित हुए। दक्षिण भारत भाषा, बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की विविधता के कारण अलग रणनीति मांगता है।

संस्थापक का क्षेत्र में रहना स्थानीय केंद्र, शिक्षक और विश्वविद्यालय साझेदारी तेज कर सकता है। विस्तार की सफलता नामांकन, भाषा सामग्री और परिणामों पर निर्भर करेगी। यह कदम कंपनी के

पैन-इंडिया मॉडल को दक्षिण में गहरा करने का प्रयास है।



D2C Silver Jewellery Brand Unniyarcha Raises ₹10 Crore, Led by Sauce In-House Craft for Daily Wear; Funds for Brand, Capacity and New Categories

Bengaluru: Direct-to-consumer silver jewellery brand Unniyarcha has raised ₹10 crore in a funding round led by Sauce VC, with Consumer Collective Atrium also participating.

Founded in 2021 by Pulkit Bhat and Divya Nambiar, the company designs and manufactures traditional and modern silver jewellery in-house. Pieces are priced between ₹1,000 and ₹3,000 and include necklaces, earrings, bangles, pendants and men's jewellery. About 70 artisans work with the brand. The founders say well-made silver should not be limited to festivals or large budgets.

Roughly half of sales come from Unniyarcha's own website, 45 per cent

from quick commerce and the rest from marketplaces. Co-founder Pulkit Bhat said in-house manufacturing has allowed the company to scale without giving up craftsmanship or margins. The new capital will go into branding and marketing, expanding manufacturing and supply-chain capacity, and adding product categories.

Co-founder Divya Nambiar described the brand as a way to carry cultural stories into everyday wear. Sauce partner Yash Dholakia said India's silver jewellery market is a \$3-4 billion opportunity that is still largely unbranded. As gold prices stay high, he said daily-wear demand is shifting toward lower-purity gold and silver.

The category is crowded with marketplace sellers. Brand recall, repeat purchase and artisan capacity will decide whether the ₹10 crore round turns a regional craft story into a national daily-wear label.



WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	23141	23881	23685	23413	23217	22945	22749	22477
BANK NIFTY	55580	57673	57172	56376	55875	55079	54578	53782
SENSEX	73896	76244	75641	74769	74166	73294	72691	71819
FINNIFTY	25095	26248	25950	25523	25225	24798	24500	24073
MIDCAP	14028	15098	14842	14435	14179	13772	13516	13109
ACC	1235	1303	1288	1261	1246	1219	1204	1177
AXISBANK	1121	1274	1265	1193	1184	1112	1103	1031
ABCAPITAL	391	422	414	402	394	382	374	362
BHARTIARTL	1789	1904	1880	1834	1810	1764	1740	1694
BHEL	422	465	453	437	425	409	397	381
BIOCON	381	408	402	392	386	376	370	360
BEL	393	412	406	400	394	388	382	376
CDSL	1317	1451	1422	1370	1341	1289	1260	1208
DATAPATTERN	4418	4871	4755	4587	4471	4303	4187	4019
ESCORTS	2850	2963	2915	2882	2834	2801	2753	2720
EICHERMOTOR	7358	7781	7675	7517	7411	7253	7147	6989
FEDERAL BANK	322	346	341	331	326	316	311	301
GRINFRAPROJECT	812	941	908	860	827	779	746	698
HDFCBANK	735	774	762	748	736	722	710	696
HCLTECH	1257	1335	1310	1284	1259	1233	1208	1182
HINDUNILVR	1935	2015	1991	1963	1939	1911	1887	1859
HAL	4795	4998	4944	4869	4815	4740	4686	4611
HYUNDAI	2115	2300	2239	2177	2116	2054	1993	1931
IOC	136	142	141	138	137	134	133	130
ICICIBANK	1328	1380	1366	1347	1333	1314	1300	1281
INFY	999	1085	1065	1032	1012	979	959	926
ITC	269	279	275	272	268	265	261	258
KOTAKBNK	402	438	429	416	407	394	385	372
LICHOUSING	565	613	595	580	562	547	529	514
LT	3878	4038	3991	3935	3888	3832	3785	3729
LUPIN	2086	2178	2157	2121	2100	2064	2043	2007
MARUTI	12071	12539	12407	12239	12107	11939	11807	11639
M&M	3030	3223	3159	3094	3030	2965	2901	2836
MGL	1074	1157	1135	1104	1082	1051	1029	998
MAZGAONDOC	2196	2347	2313	2254	2220	2161	2127	2068
PFC	338	361	355	347	341	333	327	319
RECLTD	313	321	317	315	311	309	305	303
RELIANCE	1225	1292	1272	1249	1229	1206	1186	1163
SBIN	982	1020	1010	996	986	972	962	948
SUNPHARMA	1856	1948	1920	1888	1860	1828	1800	1768
SHRIRAMFINANCE	991	1048	1034	1012	998	976	962	940
TITAN	4872	5178	5080	4976	4878	4774	4676	4572
TCS	2080	2239	2192	2136	2089	2033	1986	1930
TATAMOTORS	290	316	310	300	294	284	278	268
UPL	550	590	579	565	554	540	529	515
VALIENT	411	489	466	438	415	387	364	336
WIPRO	164	170	168	166	164	162	160	158

गौतम अडाणी फिर बने भारत के सबसे अमीर, अंबानी दूसरे स्थान पर

New Delhi: M3M द्वारा इंडिया रिच लिस्ट 2026 में गौतम अडाणी और परिवार ने मुकेश अंबानी और परिवार को पीछे छोड़कर देश के सबसे अमीर का स्थान फिर हासिल कर लिया है।

अडाणी परिवार की संपत्ति 13 प्रतिशत बढ़कर ₹9.23 लाख करोड़ हो गई। अंबानी परिवार की संपत्ति 10 प्रतिशत घटकर ₹8.63 लाख करोड़ रह गई। दोनों के बीच अंतर करीब ₹59,400 करोड़ है। पिछले पांच वर्षों में शीर्ष स्थान पांच बार बदला है।

लक्ष्मी निवास मित्तल और परिवार 93 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ ₹3.39 लाख करोड़ पर तीसरे स्थान पर आए। साइरस पूनावाला परिवार चौथे और एचसीएल की रोशनी नादर मल्होत्रा ₹2.79 लाख करोड़ के साथ पांचवें स्थान तथा देश की सबसे अमीर महिला हैं। कुमार मंगलम बिड़ला, दिलीप सांगवी और अजीम प्रेमजी शीर्ष दस में शामिल हैं।

सूची में ₹1,000 करोड़ या अधिक संपत्ति वाले 1,810 लोग हैं। कुल संपत्ति 12.8 प्रतिशत बढ़कर ₹187.5 लाख करोड़ हो गई। डॉलर अरबपतियों की संख्या रिकॉर्ड 391 पहुंच गई, पिछले वर्ष 27 नए जुड़े। स्वनिर्मित उद्यमियों का हिस्सा 70 प्रतिशत है। मुंबई में सबसे अधिक 465 नाम हैं, फिर दिल्ली और बेंगलुरु।

मूल्यांकन 24 अगस्त 2026 के शेयर भाव और अनुमानों पर आधारित है। ऐसी सूचियां बाजार के उतार-चढ़ाव से बदलती रहती हैं। भारत की संपत्ति अब पारंपरिक उद्योग के साथ एआई, डिफेंस और हरित ऊर्जा से भी जुड़ रही है।



Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.